[Shri T. Rathinavel]

Sir, the Tamil Nadu Government needs huge funds for implementing these schemes. In view of this situation, I request the Centre to bear, at least, 50 per cent of the cost of these proposed projects.

Demand to formulate a plan for development of Khambhat city in Gujarat as a port city

श्री लाल सिंह वडोदिया (गुजरात): महोदय, गुजरात राज्य में स्थित खम्भात शहर प्राचीन काल में बंदरगाह के रूप में विकसित था। उस समय इस बंदरगाह से विश्व के लगभग 84 देशों से व्यापार होता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जहांगीर की मां हज करने मक्का गई थीं, तो इसी बंदरगाह का उपयोग किया गया था और उनकी मां की निगरानी के लिए खम्भात के नवाब साहब ने दो जहाज भेजे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय इस शहर की यातायात व्यवस्था बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ थी। इसी शहर में एक मही नदी बहती है जिसकी धारा में पर्वतों से मिट्टी आदि बहकर आने लगी, जिसकी सफाई न किए जाने के कारण धीरे-धीरे नदी का धरातल ऊंचा होता चला गया, फलस्वरूप वहां पर मैदान हो गया और बंदरगाह का काम बंद हो गया। इस बंदरगाह के चालू हो जाने से अभी जो मध्य गुजरात से सौराष्ट्र जाने वालों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है, वह तो कम हो ही जाएगी, साथ ही वहां के लोगों के लिए नए-नए रोजगार मिलने भी प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे विचार से यदि वहां पर समुद्र और मही नदी के बीच बने मैदान में एक चैनल बना दिया जाए, तो खम्भात शहर को दोबारा बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा सकता है। अतः मेरा जहाजरानी मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध है कि कृपया खम्भात शहर को पुनः बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाने की कृपा करें ताकि मध्य गुजरात की जनता को इसका लाभ मिल सके।

Demand to take effective measures for strict compliance of rules under the Contract Labour Act

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): There are an estimated 18 lakhs 44 thousand contract workers working in various Central Government Departments and public sector undertakings all over the country. Estimates of such workers working in similar organizations run by State Governments are not readily available. However, both the Central and State Governments are resorting to the practice of appointment of workers both male and female on contract basis on large scale. The Central Government has received complaints regarding non-compliance of various provisions of the law which includes wages and social security benefits.

The salary or wages, holidays, hours of work and other fringe benefits differ in both regular as well as those appointed on contract basis for similar kind of works. Any violation of rules framed under the Contract Labour Act is punishable.

However, in reality, the contract workers are being exploited today. They are not treated properly. Instances have come to our notice and also in the press where the workers engaged on contract basis are treated badly by their employers.